प्रदेश को पहला बैरियर-फ्री एक्सप्रेसवे मिला, बनाने में एआई-एमसी का प्रयोग किया

लखनऊ से कानपुर तक का सफर टोल पर रुके बिना होगा

उद्घाटन

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के इतिहास में सोमवार का दिन मील का पत्थर साबित हुआ। रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे एनई-6 का लोकार्पण किया।

इसके साथ ही प्रदेश को पहला बैरियर-फ्री एक्सप्रेसवे मिल गया, जहां वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकोगनिशन (एएनपीआर+एआई) कैमरों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) रीडर आधारित निगरानी प्रणाली के जरिए चलते-चलते ही टोल की वसूली होगी। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच ढाई घंटे तक का सफर अब महज 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे सिर्फ एक नई सड़क नहीं, बल्कि देश में स्मार्ट, डिजिटल और भविष्य की परिवहन व्यवस्था की नई शुरुआत माना जा रहा है। क्योंकि, देश में पहली बार इसे बनाने में एआई-एमसी तकनीक का प्रयोग किया गया। भविष्य में देश के सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे इसी तकनीक पर बनाए जाएंगे।

साढ़े चार साल का इंतजार खत्म : 5 जनवरी 2022 को इस छह लेन (आठ लेन विस्तार योग्य) एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। निर्माण कार्य लगभग 1,645 दिन में पूरा हुआ। कई बार उद्घाटन की तिथि बदली और उपयोगिताओं के स्थानांतरण सहित तकनीकी कारणों से परियोजना में देरी हुई, लेकिन आखिरकार यह यातायात के लिए तैयार हो गई। 30 अप्रैल 2026 को यह बनकर तैयार हो गया।

पहले एनएच-27 पर था पूरा दबाव: लखनऊ और कानपुर के बीच वर्षों तक आवागमन का मुख्य आधार पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-27) रहा। पहले यह मार्ग दो लेन का था, बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से चार लेन बनाया गया। औद्योगिक, व्यावसायिक और दैनिक आवागमन के कारण इस कॉरिडोर पर ट्रैफिक दबाव रहता है।

उन्नाव में सोमवार को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। • एएनआई

एक नजर में

- **लंबाई** : 63 किमी
- **लेन** : 6 (भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित होने योग्य)
- **यात्रा समय** : 2.5 घंटे से घटकर 45–60 मिनट
- **विशेषता** : यूपी का पहला और देश का तीसरा बैरियर-फ्री एक्सप्रेस है, देश का पहला एक्सप्रेसवे जिसे एआई-एमसी तकनीक से बनाया गया
- **टोल व्यवस्था** : आरएफआईडी और एएनपीआर+एआई कैमरों से स्वतः वसूली
- **निगरानी** : एआई आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग
- **निर्माण अवधि** : करीब 1,645 दिन

लखनऊ-कानपुर हाईवे 2010 में फोर लेन हुआ

लखनऊ–कानपुर मार्ग पहले राष्ट्रीय राजमार्ग-25 (एनएच–25) था, जिसे बाद में पुराना नंबर हटा व नया नंबर देकर इसे एनएच–27 बना दिया गया। चार लेन 2004 से 2009 के बीच हुआ और 2009–10 तक पूरा कॉरिडोर फोर लेन हो गया। कई स्थानों पर सर्विस रोड, फ्लाईओवर और जंक्शन सुधार भी किए गए।

हरदोई और लखनऊ के बीच जाम खत्म होगा

हरदोई और राजधानी लखनऊ के बीच सफर अब पहले से कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-731 के पैकेज-4 के तहत करीब 32 किलोमीटर लंबे मार्ग का फोरलेन निर्माण पूरा हो गया है। इस पर 541 करोड़ खर्च किए गए हैं। यह खंड हरदोई जिले की सीमा से लखनऊ रिंग रोड तक विकसित किया गया है।

सड़क की परतों को सटीक बनाया

लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसे बनाने में ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट-मशीन एडेड कंट्रदशंस (एआई-एमसी) का उपयोग किया गया। इससे लैस मशीनों ने सड़क की परतों की मोटाई और समतलता को अत्यधिक सटीक बनाया।

देश की जरूरत अनुसार स्वास्थ्य अनुसंधान होगा

तकनीक

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में जिन बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है, उन पर केंद्रित अनुसंधान किए जाएंगे। इससे इन बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए नए उपाय किए जा सकेंगे। साथ में नई और किफायती तकनीकें भी विकसित होंगी। नई स्वास्थ्य अनुसंधान नीति में ये प्रावधान किए जा रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति (एनएचआरपी) का मसौदा जारी किया गया है। इसमें विभिन्न पक्षों से 27 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। यह पहली बार है जब देश में स्वास्थ्य अनुसंधान को लेकर नई नीति का प्रारूप जारी किया गया है।

मसौदे में देश में फैल रही बीमारियों के आधार पर चिकित्सा अनुसंधान करने, किफायती तकनीकें विकसित करने, लोगों के स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्वदेशी समाधानों पर जोर, उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का मुकाबला करने में स्वास्थ्य तंत्र को सक्षम बनाना तथा स्वास्थ्य तकनीकों के मामले में आत्मनिर्भर बनने को तरजीह दी गई है। नीति में स्वास्थ्य अनुसंधान में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि इसके जरिये स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती प्रदान की जा सके।

भारत में डेंगू, मलेरिया, तपेदिक जैसी बीमारियां बड़ी चुनौती हैं। चूंकि, पश्चिमी देशों में ये बीमारियां कम हैं, इसलिए इन पर अनुसंधान कम होते हैं। लेकिन, नई नीति के मसौदे से साफ है कि भारत ऐसी बीमारियों पर अनुसंधान तेज करेगा।

- नई स्वास्थ्य अनुसंधान नीति का मसौदा जारी
- डेंगू, मलेरिया, तपेदिक है सबसे बड़ी चुनौतियां

देश 38 S

अभिषेक के नाम के प्रयोग पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा करते हुए कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन सेलर्स व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज, शक्ल-सूरत व व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

पीएम के दौरे के दौरान धमाकों की धमकी

चंडीगढ़। खालिस्तान-समर्थक एक समूह ने कथित तौर पर ई-मेल भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब और हरियाणा दौरे के दौरान बम धमाकों की धमकी दी है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ई-मेल में धमकी दी गई है कि प्रधानमंत्री के पंजाब और हरियाणा दौरे के दौरान 17 जुलाई को चंडीगढ़ और जालंधर में विद्यालयों, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर बम धमाके किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में यूसीसी समिति ने सौंपी रिपोर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति (सेनि.) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधेयक को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

गुजरात में चांदीपुरा वायरस के सात मामले

गांधीनगर। गुजरात में पिछले कुछ हफ्तों में चांदीपुरा वायरस से संक्रमण के सात मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से तीन मरीजों की मौत हो गई और चार अन्य उपचाराधीन हैं। सभी मरीज 10 साल से कम उम्र के थे। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने राज्य में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप की समीक्षा के लिए गांधीनगर में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक की।

गंदे शौचालय पर रेलवे जवाब देगा

नई दिल्ली, एजेंसी। ट्रेनों में स्वच्छता के दावों को लेकर रेलवे बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए रेलवे ने कोच की सफाई को लेकर सभी जोन से जवाब मांगा है।

वहीं, देशभर की दैनिक रेलगाड़ियों में लगे आईसीएफ (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पीलेकोच) कोचों को अगले दो साल में पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। इनकी जगह एलएचबी (लाल कोच) लगाए जाएंगे जो ज्यादा सुरक्षित हैं।

ऋतब्रत को और समय न दें : ममता

नई दिल्ली, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में वर्चस्व हासिल करने को लेकर शुरू हुआ विवाद नए मोड़ पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि ऋतब्रत बनर्जी को संगठनात्मक चुनावों से जुड़े दावों पर जवाब देने के लिए और समय नहीं दिया जाए।

दरअसल, दो जुलाई को ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बताते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया। गुट ने कहा था कि उसने 22 जून को आयोजित विशेष अधिवेशन के बाद आयोग को इसकी जानकारी दी थी और संगठन में किए गए बदलावों को मान्यता देने का अनुरोध किया था। इस दावे के बाद निर्वाचन आयोग ने दोनों को पत्र भेजकर जवाब मांगा था।

परियोजनाओं से मोदी देंगे रणनीति को धार

पंजाब

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। पंजाब की चुनावी बिसात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से भाजपा अपने अभियान को नई गति देगी। इसके पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य का व्यापक दौरा कर संगठन को चुनावी मोड में ला दिया है। गृह मंत्री अमित शाह भी बीते दिनों राज्य का दौरा कर चुके हैं। भाजपा के भावी चुनावी एजेंडे में पंजाब बड़ा लक्ष्य है। पार्टी वहां अपनी पहली सरकार की संभावनाएं तलाश रही है।

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य में संगठन और जनाधार मजबूत करने की रणनीति तेज कर दी है। प्रधानमंत्री का आगामी पंजाब दौरा इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 17 जुलाई को पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। इसमें वह राज्य को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 125 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 110 साल पुराने विकसित जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रमुख है। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और नई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात पर जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बचाए रखने की जंग लड़ रही है, तो कांग्रेस वापसी के लिए प्रयास कर रही है। भाजपा पंजाब में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री यह दौरा उसके अभियान को नई धार देगा। भाजपा ने पंजाब के विकास को अपने अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। पार्टी अन्य राज्यों के विकास का हवाला देकर पंजाब में भी डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाकर जनता के बीच जा रही है।

पांच माह में प्रधानमंत्री का पंजाब में दूसरा दौरा

प्रधानमंत्री का पिछले पांच महीनों में पंजाब का दूसरा दौरा होने जा रहा है। इससे पहले वह एक फरवरी को जालंधर गए थे। इसके बाद अमित शाह और नितिन नवीन भी पंजाब का तीन दिन का व्यापक दौरा कर चुके हैं। अपने दौरे में नवीन ने राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर संगठन को नई ऊर्जा देने का काम किया था। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को खास तौर पर मिशन पंजाब में लगाया है।

हर वर्ग के लिए अलग अभियान चलाया

पंजाब में भाजपा का ज्यादा फोकस शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दोआबा, माझा और मालवा पर है। पार्टी ने अनुसूचित जाति, युवा, व्यापारी, किसान और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए अलग-अलग अभियान चलाए हैं। पार्टी की रणनीति स्थानीय नेतृत्व, प्रभावी उम्मीदवार और क्षेत्रीय मुद्दों पर स्पष्ट भूमिका है।

पश्चिम बंगाल में दंगाइयों की संपत्ति से भरपाई होगी

कानून

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को संगठित अपराध और हिंसक विरोध-प्रदर्शनों पर लगाम लगाने के मकसद से दो कानून लागू किए।

इन कानूनों के तहत अधिकारियों को बिना ट्रायल के संदिग्धों को हिरासत में लेने और दंगाइयों की संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई करने का अधिकार दिया गया है। 'वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट, 2026' और 'वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, 2026' राज्य विधानसभा द्वारा 29 जून को पारित किए जाने के बाद सोमवार से लागू हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि 'एंटी-गुंडा लॉ' जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को ऐसे लोगों को 12 महीने तक के लिए एहतियातन हिरासत में लेने का आदेश का अधिकार देता है।

मस्जिद दूसरी जगह ले जाएंगे : मजूमदार

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे के पास स्थित मस्जिद को दूसरी जगह ले जाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।

नामांकन रैली में भावुक हुए नरोत्तम

दतिया (मध्य प्रदेश), एजेंसी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सोमवार को दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की नामांकन रैली के दौरान मंच पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी की जीत पक्की करने के लिए वह खुद पूरे क्षेत्र में प्रचार करेंगे।

शुक्रवार को जब भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया तो मिश्रा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। मिश्रा ने कहा कि पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे 30 साल तक विधायक और 15 साल तक मंत्री रहने का मौका दिया और क्या चाहिए? पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा देगा।

जनसुराज के प्रशांत समेत 13 प्रत्याशी मैदान में उतरे

बांकीपुर उपचुनाव

पटना, प्रधान संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को 13 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इनमें जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा प्रमुख रहे।

इस सीट के लिए अब तक 23 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा (रा) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हम (सेक्युलर) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह व अन्य शामिल रहे।

इसके पहले नीरज ने नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा स्मृति पार्क में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। आवेदनों की जांच मंगलवार को होगी। नाम वापसी की तिथि 16 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान और तीन अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने पैदल तीन किलोमीटर चलकर नामांकन किया।

राहत | **पूंजीगत लागत पूरी होने के बाद भी कर रहे वसूली, सरकार की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा**

देशभर में 80 से ज्यादा टोल प्लाजा हटाए जाएंगे

■ अरविंद सिंह

नई दिल्ली। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार की एक आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देशभर में लगभग 80 से अधिक प्लाजा ऐसे हैं, जिनकी पूंजीगत लागत पूरी हो चुकी है या वे 60 किलोमीटर के भीतर गलत तरीके से वसूली कर रहे हैं। सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे ऐसे टोल प्लाजा को एक अक्तूबर से समाप्त करने का फैसला कर किया है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सूत्रों ने बताया उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड सहित दक्षिण भारत के कई टोल ऑपरेटर 60 प्रतिशत टोल माफी से बचने के लिए चालाकी करते हैं। राजमार्ग परियोजना की पूंजीगत लागत वसूली पूरी होने वाली होती है तब मंत्रालय को नया प्रस्ताव भेज देते हैं कि सेवशन पर नया फ्लाईओवर, अंडरपास या कुछ किलोमीटर की अतिरिक्त सर्विस लेन बनाने की जरूरत है। इसके बाद नए निर्माण की लागत को पुरानी लागत में जोड़ दिया जाता है। इसके बहाने वे कागजों पर यह दिखा देते हैं कि कुल पूंजीगत निवेश अभी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह वे दशकों तक जनता से पूरा 100 फीसदी टोल वसूलते रहते हैं। मंत्रालय की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में इसे पकड़ा गया है। वहीं, 60 किलोमीटर की दूरी के नियम को ताक पर रखकर सब-टोल चलाए जा रहे हैं। ऑडिट में पाया गया कि ये अवैध हैं और बिना किसी कानूनी मंजूरी के चलाए जा रहे हैं।

60 किलोमीटर के भीतर गलत तरीके वसूली भी उजागर

ऑडिट रिपोर्ट में इन पर सवाल

- दिल्ली–हरियाणा को जोड़ने वाले केएमपी के कनेक्टिंग लूप टोल प्लाजा इस ऑडिट के मुख्य निशाने पर हैं।
- दीदारगंज–फतुहा के पास (पटना–बक्सियारपुर सेक्शन– एनएच–30) दूरी के नियमों और सब–टोलिंग को लेकर लोगों ने अदालत और विभाग में शिकायतें दर्ज कराई हैं।
- मुजफ्फरपुर–बरौनी और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले कुछ विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग।
- हापुड़–मुरादाबाद रूट पर ब्रजघाट और उसके आसपास के छोटे कलेक्शन पॉइंट्स।
- कानपुर–फतेहपुर–इलाहाबाद राजमार्ग (एनएच–2) के चौड़ीकरण के दौरान पुराने स्थापित टोल और नए बाईपास टोल के बीच की दूरी कई जगह 45 से 50 किलोमीटर ही रह गई है।
- दिल्ली–देहरादून हाईवे और कुमाऊं–गढ़वाल को जोड़ने वाले मैदानी इलाकों के प्रवेश द्वार।

चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई : पहले चरण में अक्टूबर 2026 तक उन 35 टोल प्लाजा को हटाया जाएगा, जिनका अनुबंध पूरा हो चुका है और जो पूरी तरह से अवैध श्रेणी में आ चुके हैं। दूसरे चरण में 31 दिसंबर 2026 की अंतिम समय-सीमा तय की है।

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number : L74140DL1991PLC046369
Registered Office : 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi, 110 019
Corporate Office : Plot No. 3A, Sector 126, Noida 201 304, U.P., India
Website: www.hcltech.com; Telephone: +91 11 26436336
Email: investors@hcltech.com

Extract of Consolidated Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended 30 June 2026 (Unaudited)	Previous year ended 31 March 2026 (Audited)	Three months ended 30 June 2025 (Unaudited)
Total income from operations	34,579	130,144	30,349
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary item	6,108	23,058	5,189
Net profit for the period before tax	6,108	22,102	5,189
Net profit for the period after tax (refer note 5)	4,626	16,652	3,844
Net profit for the period after tax and non-controlling interest	4,624	16,642	3,843
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and non-controlling interest and other comprehensive income after tax)	4,689	20,347	5,055
Equity share capital (par value ₹ 2 each)	543	543	543
Other equity attributable to owners of the Company#	74,622	74,622	69,112
Earnings per equity share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)			
Basic (in ₹)	17.09	61.46	14.18
Diluted (in ₹)	17.06	61.36	14.17

Balances for three months ended 30 June 2026 and year ended 31 March 2026, represent balances as per the audited consolidated balance sheet for the year ended 31 March 2026 and balances for three months ended 30 June 2025, represent balances as per the audited consolidated balance sheet for the year ended 31 March 2025, as required by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Extract of Standalone Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended 30 June 2026 (Unaudited)	Previous year ended 31 March 2026 (Audited)	Three months ended 30 June 2025 (Unaudited)
Total income from operations	14,337	55,031	13,073
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary item	7,985	16,705	3,873
Net profit for the period before tax	7,985	10,024	3,873
Net profit for the period after tax	7,025	7,627	2,888
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	7,381	5,812	2,717
Equity share capital (par value ₹ 2 each)	543	543	543
Other equity#	25,355	25,355	34,397
Earnings per equity share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)			
Basic (in ₹)	25.96	28.17	10.66
Diluted (in ₹)	25.92	28.12	10.65

Balances for three months ended 30 June 2026 and year ended 31 March 2026, represent balances as per the audited standalone balance sheet for the year ended 31 March 2026 and balances for three months ended 30 June 2025, represent balances as per the audited standalone balance sheet for the year ended 31 March 2025, as required by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Notes :

1. The consolidated and the standalone financial results for the three months ended 30 June 2026 were reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 13 July 2026. The statutory auditors have issued unmodified review report on these results.
2. The Board of Directors at its meeting held on 13 July 2026 has declared an interim dividend of ₹ 12 per share.
3. **One-time impact of New Labour Codes** : Effective 21 November 2026, The Government of India has consolidated multiple existing labour legislations into a unified framework comprising four Labour Codes collectively referred to as the 'New Labour Codes'. Under Ind AS 19, changes to employee benefit plans arising from legislative amendments constitute a plan amendment, requiring recognition of past service cost immediately in the statement of profit and Loss. The New Labour Codes has resulted in estimated one time increase in provision for employee benefits of the Group and the Company of ₹ 956 crores and ₹ 948 crores (along with consequential tax benefit of ₹ 237 crores and ₹ 235 crores, resulting in decrease in profit after tax by ₹ 719 crores and ₹ 713 crores), respectively and the same has been recognized as an employee benefit expense (exceptional item) in year ended 31 March 2026.
4. **One-time impact of a material Bilateral Advance Pricing Agreement (BAPA) on Standalone financial results:** During the quarter ended 31 March 2026, the Company concluded a Bilateral Advance Pricing Agreement (BAPA) with a tax authority in foreign jurisdiction covering certain prior financial years in relation to transaction with its wholly owned subsidiary.

   Consequent to above, the Company recognised an incremental impact of ₹ 6,436 crores during the quarter ended 31 March 2026, comprising ₹ 5,733 crores pertaining to periods up to 31 March 2025, as an exceptional item and ₹ 703 crores pertaining to the nine months ended 31 December 2025, as a reduction from revenue from operations, with a corresponding adjustment in the wholly owned subsidiary.

   The above expense has resulted in a tax benefit of ₹ 1,531 crores during the quarter ended 31 March 2026 which includes ₹ 1,317 crores for the period upto 31 March 2025 and ₹ 214 crores for the nine months ended 31 December 2025.

   Accordingly, the net impact has resulted in a decrease in profit after tax of ₹ 4,905 crores for the quarter ended 31 March 2026 which includes ₹ 4,416 crores for the period upto 31 March 2025 and ₹ 489 crores for the nine months ended 31 December 2025.
5. Profit (loss) for the period/year, excluding one-time impacts of New Labour Codes and material BAPA and related tax impact,
   a. For the Group is ₹ 17,371 crores for the year ended 31 March 2026.
   b. For the Company is ₹ 12,756 crores for the year ended 31 March 2026.
6. **Acquisition of Jaspersoft, a business unit of Cloud Software Group (CSG)** : On 22 December 2025, the Group had signed a definitive agreement to carve-out and acquire Jaspersoft, a business unit of CSG providing a leading embedded analytics and pixel perfect reporting platform, for ₹ 2,275 crores ($240 million). The transaction completed on 1 July 2026 post receipt of applicable regulatory approvals and will be accounted for in next quarter. Through this acquisition, the Group has acquired a comprehensive business intelligence and reporting platform and a large, global developer community comprised of data engineers and architects.
7. Financial results for all the periods presented have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended from time to time) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
8. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com, and on the Company's website, www.hcltech.com, and these can also be accessed through the QR code given below.

By the order of the Board of Directors for HCL Technologies Limited

Roshni Nadar Malhotra
Chairperson
DIN - 02346621

C. Vijayakumar
Chief Executive Officer and Managing Director
DIN - 09244485

Shiv Walia
Chief Financial Officer

Noida (U.P.), India
13 July 2026

HCL